भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 328
जिसका उत्तर मंगलवार 5 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल उद्योग में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी

328 **श्री प्रहलाद जोशीः**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि चूंकि भारतीय ऑटोमोबाइल पुनर्विनिर्माण बाजार और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का महत्व और अधिक हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय ऑटो विनिर्माताओं को नवीनतम प्रौद्योगकी की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत को वास्तव में वैश्विक ऑटो विनिर्माता/उत्पादक बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपकरण प्राप्त करने हेतु ऑटो उद्योग को सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कार विनिर्माता, 7वां सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता और दुपहियों का सबसे बड़ा विनिर्माता है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने ऑटो घटक उद्योग के साथ वाहनों में वैश्विक ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों को अपनाया है और परिणामस्वरुप नवोन्मेषी विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो उच्च मात्रा के ऑटोमेशन की तुलना में अधिक जन अभिमुख हैं जो विश्व में सभी जगह प्रचलित हैं।

(ख): जी हां, ऑटोमोटिव उद्योग में तेजी से बदलती उत्पाद प्रौद्योगिकियों और कम होते जीवाश्म ईधन संसाधनों, इनकी उच्च आयात लागत, पर्यावरणीय निम्नीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे संबंधित मुद्दों के मुद्देनजर, पारम्परिक आईसी इंजन आधारित वाहनों से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, ईधन सैलों जैसी नई ड्राइ व ट्रेन प्रौद्योगिकियों की अपनाना समय की मांग है। इस प्रकार, उद्योग को ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों तथा बैटरी प्रबंधन प्रणालियों के लिए लिथियम आयन बैटरियों, इलेक्ट्रिक मोटरों जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित करनी होंगी।

(ग) और (घ): जी हां, सरकार ने मिशन मोड में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकासित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, 2013 आरंभ किया है। अनुवर्ती के रूप में, मांग सृजन, इवी इकोप्रणाली/अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015 में फेम योजना आरंभ की गई। इस योजना (फेम) के द्वितीय चरण में अनुसंधान एवं विकास प्रयासो सहित मांग और आपूर्ति पर अनेक हस्तक्षेपों के साथ ईवी उद्योग को बढ़ावा देने की परिकल्पना है।

इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग, ऑटोमोबाइल एवं सम्बंध उद्योग विकास परिषद (डीसीएएआई) निधि के माध्यम से उत्पाद तथा परीक्षण अवसंरचना विकास के लिए दिए गए अनुदानों के माध्यम से समय-समय पर ऑटोमोटिव उद्योग के लिए प्रौद्योगिकिय हस्तक्षेपों की सहायता करता है।

*****